3

एम्स भोपाल में 150वें वर्ष 'वंदे मातरम्' उत्सव

5

जनप्रिय नेता है गजेन्द्र सिंह शेखावत

6

भाऊ साहेब शासकीय मवि में युवा उत्सव

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 27 प्रति सोमवार, 10 नवंबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

विक्रमादित्य शोध पीठ भटक रही अपने उद्देश्यों से, उठ रहे सवाल

श्रीराम तिवारी ने विभाग को बना दिया राजनीति का अड्डा

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

एडिटर

मध्यप्रदेश सांस्कृतिक रूप से अपनी समृद्ध परंपरा, लोक कला, शिल्प, संगीत और नाट्य विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सांस्कृतिक संस्थाएँ चाहे वह भारत भवन हो, अलीराजपुर की जनजातीय अकादमी हो या विक्रमादित्य शोध पीठ। सभी ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु हाल के वर्षों में यह चर्चा तेज हुई है कि इन संस्थाओं की प्राथमिकताएँ अपने मूल उद्देश्य से भटककर केवल आयोजनों और तात्कालिक दिखावे तक सीमित हो गई हैं।

विक्रमादित्य शोध पीठ शोध से अधिक "शो" का पीठ?

मध्यप्रदेश सच में अजब भी है और गजब भी। यहाँ इतिहास उतना ही जिंदा है जितनी राजनीति। वर्षों

से धूल खा रही विक्रमादित्य शोध पीठ अचानक एक दिन जाग उठी। पीठ को मिल गए श्रीराम तिवारी। और फिर क्या था, पीठ में लूटमार मच गई। पीठ का काम शोध करना है लेकिन अब इसका काम केवल शो बाजी करना हो गया है। बड़े-बड़े आयोजन कर सरकारी पैसों का दुरूपयोग करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और श्रीराम तिवारी की जोड़ी ने इस पुरातन संस्थान में ऐसा प्राण फूंका कि पीठ अब शोध नहीं, बल्कि "शो" का केंद्र बन गई है। खास बात यह है कि यह शोध पीठ संस्कृति परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। इस परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल शोध पर कार्य करने के लिए बजट दिया। बड़े-बड़े एवेंट के लिए नहीं दिया। कभी यह शोध पीठ संस्कृति और इतिहास के गहन अध्ययन का केंद्र हुआ करती थी। पर अब इसमें शोध कम, "शो" ज्यादा हैं। पहले यहाँ विद्वान आते थे, अब विज्ञापनदाता आते हैं। पहले यहाँ ग्रंथ छपते थे, अब पोस्टर और बैनर छपते हैं। (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खेती, संस्कृति और विकास के संगम से हुआ नये छत्तीसगढ़ का अभ्युदय

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ हमेशा से भारत की कृषि प्रधान आत्मा का प्रतीक रहा है। धान के खेतों से लेकर गांव की चौपालों तक, यहां की मिट्टी में मेहनत, परंपरा और संस्कृति एक साथ सांस लेती हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को "धान का कटोरा" कहा जाता है क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति तीनों की धुरी किसान और खेती हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस कृषि परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है "गांव, गरीब और किसान" शासन की पहली प्राथमिकता हैं। यही सोच छत्तीसगढ़ की

नीतियों में भी झलकती है। बीते डेढ़ वर्षों में सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई नीतिगत फैसले लिए हैं, जिन्होंने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि ग्रामीण समाज में विश्वास और उत्साह का वातावरण भी बनाया है।

किसानों के हित में ठोस कदम

राज्य सरकार का सबसे बड़ा उपलब्धि संकेतक है धान खरीदी का रिकॉर्ड स्तर। बीते खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जो अब तक का सर्वोच्च आँकड़ा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि सरकार ने किसानों के पसीने का पूरा मूल्य दिया है। (शेष पेज 2 पर)

कमलनाथ का विज़न: नये मध्य प्रदेश निर्माण का संकल्प

प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता, क्या कमलनाथ के विजन को अपना सकती है सरकार?

-विजया पाठक

मध्य प्रदेश ने उत्साह और भव्यता के साथ 01 नवंबर को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया। यह दिवस केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और एक उन्नत भविष्य की आकांक्षा का प्रतीक है। जब प्रदेश जश्न में डूबा होता है, तो यह स्वाभाविक है कि हम आगे की दिशा, विजन और दूरदर्शिता पर भी विचार करें। प्रदेश को एक उन्नत भविष्य की ओर ले जाने के लिए केवल उत्सव पर्याप्त नहीं है, इसके लिए एक स्पष्ट, परिणाम उन्मुख विजन और उसे क्रियान्वित करने वाला दूरदर्शी नेतृत्व चाहिए।

यह दूरदर्शिता जो प्रदेश की युवाशक्ति, किसान वर्ग और महिलाओं के उत्थान पर केंद्रित हो, जो हमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विजन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके 15 माह के कार्यकाल ने यह साबित किया कि एक संकल्पित और अनुभवी नेतृत्व क्या हासिल कर सकता है, भले ही कार्यकाल की अवधि सीमित रही हो। कमलनाथ ने हमेशा प्रदेश को देश के नक्शे पर एक आर्थिक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने का स्वप्न देखा। उनका विजन केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि ठोस जमीनी बदलावों पर आधारित था। (शेष पेज 7 पर)

संस्कृति विभाग की अकादमियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता

(पेज 1 का शेष)

अब शोध पत्र नहीं, प्रेस नोट जारी होते हैं। श्रीराम तिवारी जबसे संस्कृति विभाग में आये हैं तबसे यह कला, संस्कृति का नहीं बल्कि राजनीति का अखाड़ा बन गया है।

शोध और अध्ययन के उद्देश्य से स्थापित संस्थाएँ

विक्रमादित्य शोध पीठ जैसी संस्थाएँ राज्य में संस्कृति, इतिहास और दर्शन के गहन अध्ययन के लिए स्थापित की गई थीं। इनका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन भारतीय परंपराओं, साहित्य, कला और समाज की जड़ों को समझना और उस पर आधुनिक दृष्टिकोण विकसित करना। परंतु आज ऐसे कई संस्थान शोध और अध्ययन से अधिक अपने आयोजनात्मक स्वरूप के लिए पहचाने जा रहे हैं।

बजट और पारदर्शिता की चुनौती

संस्कृति विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को हर वर्ष सरकार से पर्याप्त बजट मिलता है। यह राशि कला, अनुसंधान और परंपरा संरक्षण के लिए होती है, किंतु इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही पर कई बार प्रश्न उठे हैं। यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं के वित्तीय लेन-देन, आयोजन खर्च और अनुदान वितरण को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक शोध परियोजना और आयोजन का विवरण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए ताकि नागरिक समाज और कला समुदाय दोनों ही उसकी समीक्षा कर सकें।

अकादमियों के उद्देश्य और वर्तमान स्थिति

मध्यप्रदेश में संगीत, नाट्य, ललित कला, जनजातीय कला, भाषा और साहित्य से जुड़ी कई अकादमियाँ कार्यरत हैं। ये अकादमियाँ राज्य की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, परंतु इनका कार्य अब शोध और संरक्षण से अधिक सीमित आयोजनों तक सिमट गया है। कला की निरंतरता केवल कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि नई पीढ़ी में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परंपरा के हस्तांतरण से होती है। अकादमियों को अब यह सोचना होगा कि वे अपने संसाधनों का प्रयोग कलाकारों के कौशल विकास, कला शिक्षा और नवाचार में कैसे करें।

विक्रमादित्य शोध पीठ को दिशा की आवश्यकता

हाल में विक्रमादित्य शोध पीठ को लेकर जो भी चर्चाएँ सामने आई हैं। चाहे वे बजट के विस्तार की हों या नए आयोजनों की। वे एक बड़े विमर्श का संकेत देती हैं कि सांस्कृतिक संस्थाओं को अपनी भूमिका पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। यह स्वागत योग्य है कि प्रदेश स्तर पर शोध और आयोजन को लेकर उत्साह बढ़ा है, किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे प्रयासों की दिशा स्पष्ट और उद्देश्य शुद्ध हो। यदि किसी भी संस्थान की प्राथमिकता "कार्यक्रम" बन जाए और "शोध" पीछे छूट जाए, तो वह अपने नाम और पहचान दोनों के साथ न्याय नहीं कर पाता।

नवाचार और स्थानीय सहभागिता

संस्कृति के संरक्षण का अर्थ केवल अतीत को सहेजना नहीं, बल्कि वर्तमान में उसे जीवित रखना है। यदि शोध पीठ और अकादमियाँ ग्रामीण, जनजातीय और शहरी समुदायों को जोड़ेंगी, तो न केवल उनकी उपयोगिता बढ़ेगी, बल्कि सांस्कृतिक चेतना भी गहरी होगी। स्थानीय कलाकारों और शोधकर्ताओं को अवसर देकर "जन-संस्कृति" को "राज्य-संस्कृति" से जोड़ा जा सकता है। विक्रमादित्य शोध पीठ और अन्य अकादमियों को अब आत्ममंथन की जरूरत है कि वे अपने उद्देश्यों को किस दिशा में ले जा रही हैं। केवल आयोजनों की चकाचौंध में या संस्कृति की आत्मा की खोज में। यदि इन संस्थाओं ने अपनी दिशा स्पष्ट रखी और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, तो मध्यप्रदेश न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहेगा, बल्कि प्रशासनिक और नैतिक दृष्टि से भी एक आदर्श उदाहरण बनेगा। यही सच्चे अर्थों में "संवेदनशील और सशक्त मध्यप्रदेश" की पहचान होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खेती, संस्कृति और विकास के संगम से हुआ नये छत्तीसगढ़ का अभ्युदय

(पेज 1 का शेष)

कृषि नीति को किसान-केंद्रित बनाते हुए, सरकार ने पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की है और प्रति क्विंटल 3100 रुपए का समर्थन मूल्य दिया है। यह कदम किसानों के सम्मान और समृद्धि दोनों को सुनिश्चित करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संकल्प को निभाते हुए पिछली सरकार के बकाया बोनस 3716.38 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरित कर दिए। इस निर्णय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार किया। यह कदम बताता है कि सरकार राजनीति नहीं, बल्कि नीति के माध्यम से विश्वास बहाल कर रही है।

कृषि से अर्थव्यवस्था तकः विकास का मजबूत आधार

कृषि का देश की जीडीपी में योगदान भले घटा हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह अब भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यही कारण है कि सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कई स्तरों पर कार्य किया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब किसान खुशहाल होंगे, तभी प्रदेश का व्यापार और उद्योग भी गति पकड़ेंगे। यही कारण है कि सरकार "ग्रामीण समृद्धि से औद्योगिक विकास" के मॉडल पर काम कर रही है।

परंपरा और प्रगति का प्रतीक पर्व

छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ उसकी खेती में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति में भी निहित है। हरेली त्यौहार इस पहचान का सबसे सशक्त उदाहरण है। सावन अमावस्या को मनाया जाने वाला हरेली पर्व कृषि जीवन, लोक परंपरा और सामाजिक एकता का उत्सव है। इस दिन किसान अपने औजारों हल, कुदाल, फावड़ा, गैंती आदि की पूजा करते हैं। यह पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि उस श्रम के प्रति आभार का प्रतीक है, जो धरती को अन्नदायी बनाता है। माताएँ गुड़ का चीला बनाती हैं, पशुधन को नहलाकर औषधीय आटे की लोंदी खिलाई जाती है, और पूरे गांव में आनंद का वातावरण बनता है। हरेली का यह लोकपर्व बताता है कि छत्तीसगढ़ का विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि संस्कृति के संरक्षण में भी निहित है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इन लोक परंपराओं को सम्मान देने और उन्हें राज्य के विकास-नैरेटिव का हिस्सा बनाने का काम किया है।

गेड़ी की परंपरा और नई पीढ़ी का जुड़ाव

हरेली पर्व का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है गेड़ी बांस से बना वह लोकखेल जो आनंद, संतुलन और ग्रामीण कौशल का प्रतीक है। गेड़ी पर चढ़ना केवल खेल नहीं, बल्कि परिश्रम और संतुलन की शिक्षा भी है। पूर्व में गांवों में बच्चे बढ़ई के घर से गेड़ी मंगाते थे और दिनभर आनंद लेते थे। आज जब गांवों की गलियां पक्की हो गई हैं, तब भी यह परंपरा जीवित है। सरकार ने ग्रामीण संस्कृति को सहेजने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक उत्सवों और ग्रामीण खेलों को बढ़ावा दिया है। यह प्रयास नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का माध्यम है।

लोकजीवन में विज्ञान और परंपरा का संगम

हरेली पर्व का एक और पहलू है पशुधन की देखभाल और वनौषधि का उपयोग। इस दिन किसान अपने पशुओं को औषधीय लोंदी खिलाते हैं, जिससे रोगों से बचाव होता है। यादव समाज जंगलों से जड़ी-बूटियाँ लाकर किसानों को वितरित करता है। यह सामुदायिक सहयोग और जैविक चिकित्सा का अद्भुत उदाहरण है जो आज की "सस्टेनेबल एग्रीकल्चर" की अवधारणा से मेल खाता है। प्रदेश सरकार भी इस परंपरा को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ रही है। पशुधन विकास और जैविक खेती को प्रोत्साहन देकर यह प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बने।

राजनीतिक दृष्टि से सशक्त संदेश

राजनीतिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव की राजनीति को भी मजबूती दी है। उनका दृष्टिकोण यह संकेत देता है कि शासन तभी सफल होता है जब वह जनता की संस्कृति, मेहनत और जीवनशैली को समझता है। धान खरीदी, बोनस भुगतान, सिंचाई विस्तार और ग्रामीण रोजगार योजनाएँ सिर्फ योजनाएँ नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्वसनीयता का प्रतीक बन चुकी हैं। साय सरकार की नीति का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि उसने किसान को "लाभार्थी" नहीं, बल्कि "साझेदार" बनाया है। जहाँ अधिकांश सरकारें किसान को सब्सिडी या मुआवजे तक सीमित कर देती हैं, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान को अर्थव्यवस्था का सक्रिय भागीदार बनाया है। यही बदलाव "किसान-केन्द्रित राजनीति" से "किसान-प्रधान अर्थनीति" की ओर बढ़ने का संकेत है।

संस्कृति और अर्थव्यवस्था का समावेश

छत्तीसगढ़ ने यह दिखाया है कि विकास का मॉडल केवल उद्योग या शहरीकरण से नहीं बनता। एक सशक्त राज्य वह होता है, जो अपने ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ करे, कृषि को सम्मान दे और लोक संस्कृति को जीवित रखे। मुख्यमंत्री साय का नेतृत्व इसी सोच पर आधारित है "संवेदनशील शासन, सशक्त किसान और सांस्कृतिक गौरव।" सरकार ने हरेली जैसे लोकपर्वों को सरकारी कैलेंडर में सम्मानजनक स्थान दिया है, जिससे परंपरा और प्रशासन के बीच संवाद का सेतु बना है।

नई दिशा की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

आज जब देश के कई हिस्सों में कृषि संकट की चर्चा होती है, तब छत्तीसगढ़ एक उम्मीद की कहानी बनकर उभर रहा है। यहाँ सरकार केवल योजनाएँ नहीं, बल्कि संवेदनशील दृष्टि लेकर आगे बढ़ रही है। किसानों को उचित मूल्य, बोनस, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक सम्मान यह सब मिलकर एक "संतुलित विकास मॉडल" की परिभाषा रच रहे हैं। हरेली जैसे पर्व अब केवल त्योहार नहीं, बल्कि "नीति के प्रतीक" बन चुके हैं जो यह याद दिलाते हैं कि धरती से जुड़ाव ही असली समृद्धि है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की यह यात्रा बताती है कि जब शासन और संस्कृति एक साथ चलते हैं, तो विकास केवल योजनाओं तक नहीं, बल्कि जनजीवन तक पहुंचता है।

वन विभाग की कार्रवाई से आजीविका संकट में, भूमिहीन महिलाओं ने माँगे पट्टे

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह, देवरीकला। वन परिक्षेत्र गौरझामर द्वारा प्लांटेशन (वृक्षारोपण) के लिए वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के बाद, ग्राम गोपालपुरा की बड़ी संख्या में भूमिहीन खेतिहर महिलाओं ने उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को एक हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपकर भूमि के पट्टों की मांग की है।

क्या है मामला?: ज्ञापन में बताया गया है कि गोपालपुरा के 50 से अधिक परिवार भूमिहीन हैं और वे कृषि मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। इन परिवारों ने कथित तौर पर वन भूमि पर कब्जा करके उसे कृषि योग्य बनाया और पीढ़ियों से खेती कर अपना भरण-पोषण करते आ रहे थे। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वन परिक्षेत्र गौरझामर ने 2 और 3 नवंबर को बिना किसी पूर्व सूचना के कब्जे वाली वन भूमि की फसलों को नुकसान पहुँचाया और प्लांटेशन के लिए गड्ढे खोदना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई से उनकी आजीविका पर बड़ा संकट आ गया है।

भूमि के पट्टों की मांग: प्रभावित महिलाओं ने एसडीएम से मांग की है कि सभी खेतिहर मजदूरों को न्याय देते हुए उन्हें खेती के लिए भूमि के पट्टे उपलब्ध कराए जाएं।

जनप्रतिनिधि का समर्थन: इस गंभीर मामले पर जिला पंचायत सदस्य जनकरानी करण सिंह गौड़ ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "आदिवासी और गरीब परिवारों पर बिना सूचना के ऐसी कार्यवाही उचित नहीं है। ये लोग पीढ़ियों से इसी भूमि पर रहकर खेती कर रहे हैं। वन विभाग की कार्यवाही से उनकी आजीविका पर संकट आ गया है।" श्रीमती गौड़ ने सरकार से आग्रह किया कि इन परिवारों को सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित करने के लिए शीघ्रता से भूमि के पट्टे उपलब्ध कराए जाएँ। ज्ञापन सौंपने वाली महिलाओं में आशा रानी, अमर, दशरथ, मालती, नबवी, प्रीति, गीता, नीमा, कुवरवाई, अनीता, लक्ष्मी, वंदना सहित बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर महिलाएं शामिल थीं।

उत्तराखंड सरकार की प्रमुख योजनायें और उनके लाभ

धामी सरकार की नीतियों और निर्णयों से आत्मनिर्भर बन रहा प्रदेश

-संवाददाता

जगत प्रवाह. देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने प्रदेश को विकास के उच्च पायदान पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। सरकार की सफल नीतियों और निर्णयों के कारण रोजगार के साथ-साथ आर्थिक रूप संबल मिल रहा है। प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। उत्तराखंड कई रणनीतिक अभियानों के माध्यम से औद्योगिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रहा है और साथ ही विनिर्माण क्षेत्र से भी लाभ उठा रहा है। उत्तराखंड सरकार की योजनाएँ परिवर्तनकारी साबित हुई हैं। ये सरकारी पहल न केवल उद्यमियों को सशक्त बनाने में मदद कर रही हैं, बल्कि रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने और राज्य में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने में भी मदद कर रही हैं। विनिर्माण व्यवसायों के लिए उत्तराखंड सरकार की योजनाओं के लाभ बहुआयामी हैं। विनिर्माण क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार के लाभ केवल सब्सिडी और कर लाभ तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि कौशल विकास, बुनियादी ढाँचे और स्थिरता तक भी फैले हुए हैं। उत्तर भारत में अपना आधार बनाने पर विचार कर रहे किसी भी उद्यमी या उद्योगपति के लिए, उत्तराखंड सरकार की

योजनाओं के लाभों को जानना, स्केलेबल और टिकाऊ विकास की दिशा में एक सही कदम हो सकता है। उत्तराखंड तेजी से एक पर्यटन स्थल के बजाय औद्योगिक विस्तार और विनिर्माण नवाचार के लिए एक भूमि के रूप में उभर रहा है, जिसका श्रेय उत्तराखंड सरकार के लाभों को जाता है जो इसके आर्थिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखे हुए हैं। उत्तराखंड में व्यवसाय स्थापित करने या विस्तार करने के इच्छुक उद्यमी और उद्योगपति निम्नलिखित लाभ उठा सकते हैं:

वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी: उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएँ, जैसे पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और राज्य जीएसटी प्रतिपूर्ति, के अंतर्गत आती हैं। इससे विनिर्माण इकाइयों की स्थापना लागत में सीधे तौर पर कमी आएगी और यह क्षेत्र नए व्यापारियों के लिए आर्थिक रूप से आकर्षक बन जाएगा।

कर छूट और रियायतें: उत्तराखंड सरकार की योजनाओं के लाभों में एक और प्रमुख बात कर छूट की है। कुछ योजनाओं के तहत, विनिर्माण उद्योगों को भूमि पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क और बिजली दरों से छूट मिलती है। इस तरह की कर छूट ऊपरी खर्चों को कम करने के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

औद्योगिक पार्क और संपदा: उत्तराखंड सरकार की इस योजना के लाभों में विशिष्ट औद्योगिक पार्क और प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है। ये पार्क सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और अपशिष्ट निपटान प्रणालियों से सुसज्जित हैं, इन सुविधाओं को विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एक मजबूत आधार माना जा सकता है।

बिजली और कनेक्टिविटी लाभ: उत्तराखंड सरकार की योजनाओं के लाभों में से एक, जिस पर अक्सर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, निर्बाध बिजली आपूर्ति और कनेक्टिविटी का बुनियादी ढांचा है। राज्य ने सड़कों और रेलवे के बुनियादी ढांचे के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जबरदस्त प्रयास किए हैं, जो लॉजिस्टिक्स-आधारित विनिर्माण के लिए एक बड़ा लाभ है।

रोजगार के लिए सब्सिडी: रोजगार के लिए सब्सिडी तक फैले हुए हैं। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाले उद्योग सरकारी कार्यक्रमों के तहत वेतन और ईपीएफ अंशदान की प्रतिपूर्ति का भी लाभ उठा सकते हैं।

तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान: सरकार ने कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। उत्तराखंड सरकार की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित कुशल जनशक्ति की तत्काल उपलब्धता है, जिससे विनिर्माण दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम: इस पहल का लाभ यह था कि डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक तेज समाधान उपलब्ध हुआ। उद्यमी एक ही पोर्टल के माध्यम से भूमि, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते थे, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हुई।

समर्पित उद्योग हेल्पडेस्क: परामर्श और समस्या निवारण के लिए समर्पित उद्योग सहायता डेस्क की मौजूदगी है, जिससे परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन में वृद्धि होगी।

पर्यावरण के अनुकूल नीतियां: राज्य हरित विनिर्माण को भी बढ़ावा दे रहा है। अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था, सौर ऊर्जा के उपयोग और जल पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

पर्यावरण-प्रमाणन के लिए प्रोत्साहन: जो भी विनिर्माण में स्थिरता का पालन करेगा और पर्यावरण-प्रमाणन प्राप्त करेगा, उसे और भी पुरस्कृत किया जाएगा। ईएसजी लक्ष्यों पर केंद्रित व्यवसायों के लिए उत्तराखंड सरकार की योजनाओं का यह सबसे आशाजनक लाभ है।

एनसीआर और उत्तर भारत से निकटता

दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य भागों जैसे प्रमुख बाजारों के निकट अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण, उत्तराखंड सरकार की योजना के लाभ कम रसद लागत के साथ विशाल ग्राहक आधार तक सस्ती पहुंच प्रदान करते हैं।

स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता: उत्तराखंड सरकार की योजनाओं के लाभों में एक महत्वपूर्ण बिंदु जड़ी-बूटियों, खनिजों और वन उपज जैसे कच्चे माल की आसान उपलब्धता है जो कृषि आधारित और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण इकाइयों को समर्थन प्रदान करते हैं।

एम्स भोपाल में 150वें वर्ष 'वंदे मातरम्' उत्सव की शुरुआत

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल में 7 अगस्त 2025 को 'वंदे मातरम्' के 150वें वर्ष के राष्ट्रीय उत्सव की शुरुआत की गई। इस दौरान आयोजित राष्ट्रीय वेबकास्ट और माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को संस्थान के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से सीधा प्रसारित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से 'वंदे मातरम्' का गायन किया। यह प्रस्तुति शैक्षणिक ब्लॉक और अस्पताल परिसर के ऑडियो-विजुअल सिस्टम पर एक साथ प्रदर्शित की गई, जिससे परिसर में एकता और देशभक्ति का सशक्त वातावरण बना। यह आयोजन वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक रहा। उत्सव का प्रथम चरण 7 से 14 नवंबर 2025 तक निर्धारित है। इस अवसर पर 'वंदे मातरम्' के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और राष्ट्रीय एकता, साहस तथा राष्ट्रभक्ति को प्रेरित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में प्रो. (डॉ.) माधवानन्द कर (कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ, एम्स भोपाल) श्री संदेश कुमार जैन (उप निदेशक- प्रशासन), डॉ. रेहान उल हक (डीन- शोध), डॉ. वैशाली वाल्के (डीन- परीक्षा), विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ संकाय सदस्य, अधिकारी, प्रशासनिक एवं नर्सिंग स्टाफ, छात्र और शोधकर्ता उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने राष्ट्रीय गौरव, एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ का सम्मान

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर मध्यप्रदेश की छतरपुर जिले की घुवारा की क्रांति गौड़ का सम्मान किया और एक करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि दी। महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता की विजय यात्रा में भारत को पहली बार विश्व विजेता बनने में क्रांति गौड़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश की बेटियों ने आईसीसी महिला एक दिवसीय वनडे वर्ल्ड कप-2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत के उच्चतम प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का यह अभूतपूर्व प्रमाण है। साथ ही प्रदेश में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए क्रियान्वित योजनाओं का प्रतिफल भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय टीम पहली बार आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन बनी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी खिलाड़ियों और देशवासियों को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस ऐतिहासिक जीत में प्रदेश की बेटी और टीम की ऑलराउंडर क्रांति गौड़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऑल राउंडर क्रांति ने पाकिस्तान के खिलाफ (ग्रुप स्टेज) मैच में भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। इस मुकाबले में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। बुंदेलखंड की बेटी क्रांति गौड़ घरेलु क्रिकेट के साथ अंतरराष्ट्रीय और डब्ल्यूपीएल में अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से झंडे गाड़ रही हैं। वे परिवार में 6 भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं।

प्रदेश में SIR के नाम पर हो रहा मज़ाक: कमलनाथ

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि मध्य प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया दोषपूर्ण है और उसने पूरी प्रक्रिया का मज़ाक बना दिया है। निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश सरकार ने जिस आधी-अधूरी तैयारी के साथ प्रदेश में मतदाता सूचियों की जाँच अर्थात SIR की प्रक्रिया शुरू की है, उसने मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया का मज़ाक बना दिया है। प्रदेश के बहुत से ज़िलों में मतदाता BLO का इंतज़ार कर रहे हैं और BLO फ़ॉर्म मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हालत यह है कि ज़िलों में अभी तक फ़ॉर्म के प्रिंटआउट तैयार नहीं हुए हैं और न BLO को दिए गए हैं। जहाँ कहीं फ़ॉर्म दिए भी जा रहे हैं, वे आधे अधूरे भरे हैं। 2003 की मतदाता सूची BLO के पास उपलब्ध नहीं है और वे आशा कर रहे हैं कि मतदाता ही ख़ुद इंटरनेट से जाँच करके यह बताएँ कि उनका नाम तब था या नहीं था।

मध्य प्रदेश जैसी ग्रामीण आबादी वाले राज्य में जनता के ऊपर इंटरनेट से 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम ढूँढने की ज़िम्मेदारी डालना वोटर के साथ सरासर अन्याय है। भारत के संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि नागरिकों को मतदाता बनाना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है। इसलिए आयोग ने जो बातें काग़ज़ पर कहीं है, उनका ज़मीन पर भी पालन करे।

इतने शॉर्ट नोटिस पर और इतनी कम अवधि में SIR करना पूरी तरह तुग़लक़ी फ़रमान है। लेकिन न जाने किस नीयत के कारण आयोग इस काम में जुटा हुआ है। अगर इसी तरह की हीलाहवाली के साथ SIR किया गया तो इसमें संदेह नहीं है कि मतदाता सूची न्यायपूर्ण तरीक़े से नहीं बन पाएगी और प्रदेश के मतदाताओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं आयोग को और सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि इस हीलाहवाली के मुखौटे के पीछे वोट चोरी का षड्यंत्र ना करें। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता हर स्तर पर संघर्ष के लिए तैयार है।

सम्पादकीय

बिहार चुनाव में क्या बाजी मार लेगी आरजेडी?

बिहार की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। सत्ता की जंग में पुराने खिलाड़ी फिर मैदान में उतर चुके हैं जनता दल (यू) अपने अनुभवी नेता नीतीश कुमार के साथ, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठित चुनावी मशीनरी के साथ, और दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अपने युवा चेहरे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक बार फिर सत्ता की कुर्सी को छूने का सपना देख रही है। सवाल यही है क्या इस बार आरजेडी बाजी मार पाएगी? तेजस्वी यादव आज आरजेडी के सबसे बड़े ताकत हैं। उन्होंने 2020 के चुनाव में लगभग 75 सीटें जीतकर पार्टी को मुख्य विपक्ष की भूमिका तक पहुंचाया था। तब से उनका कद लगातार बढ़ा है। वे अब केवल "लालू के बेटे" नहीं, बल्कि "विकल्प के नेता" के रूप में देखे जाने लगे हैं। उनके भाषणों में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रवासी श्रमिकों की चिंता जैसे मुद्दे प्रमुखता से रहते हैं।

तेजस्वी की यह रणनीति एक नई राजनीतिक भाषा गढ़ने की कोशिश है जो जातिगत सीमाओं से परे जाकर युवाओं और आम मतदाताओं से जुड़ती है। आरजेडी ने महसूस किया है कि केवल यादव-मुस्लिम समीकरण के भरोसे अब सत्ता हासिल करना कठिन है। इसलिए पार्टी ने अब अति पिछड़ा वर्ग, दलित और ऊपरी जातियों के बीच भी संवाद बढ़ाने की मुहिम शुरू की है। बिहार की राजनीति में आरजेडी का सामाजिक आधार सबसे स्थायी रहा है। यादव और मुस्लिम समुदायों में पार्टी की जड़ें गहरी हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में आरजेडी का नेटवर्क अभी भी मजबूत है। पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय रहते हैं, और लालू यादव की विरासत अब भी उस वर्ग के बीच भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम है। विपक्ष में रहते हुए भी आरजेडी ने लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखा है चाहे वह केंद्र सरकार की नीतियों पर विरोध हो या राज्य सरकार की विफलताओं पर सवाल उठाना। इससे पार्टी ने "जनता की आवाज" की छवि बनाई है।

आरजेडी की राह में कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले, बिहार की राजनीति अब केवल जातिगत समीकरणों तक सीमित नहीं रही। युवा मतदाता अब रोजगार, शिक्षा, उद्योग और प्रवास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने लगा है। अगर आरजेडी ने इन पर ठोस नीति और क्रियान्वयन की झलक नहीं दी, तो उसका 'बदलाव' का नारा खोखला साबित हो सकता है। दूसरी चुनौती गठबंधन की है। कांग्रेस और वाम दलों के साथ तालमेल रखना, सीट बंटवारे में मतभेदों को रोकना और एकजुट अभियान चलाना पार्टी के लिए कठिन काम होगा। अगर विपक्षी गठबंधन में खींचतान रही तो लाभ एनडीए को मिल सकता है।

तीसरी चुनौती आती है तीसरे विकल्प से प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जैसे नए समूहों से, जो साफ-सुथरी राजनीति और युवाओं के आकर्षण का दावा कर रहे हैं। अगर इन दलों ने कुछ प्रतिशत वोट भी काट लिए, तो उसका नुकसान सीधे आरजेडी को होगा। नीतीश कुमार लगभग दो दशकों से बिहार की सत्ता में किसी न किसी रूप में बने हुए हैं। उनके विकास मॉडल की चमक भले फीकी पड़ी हो, लेकिन एक स्थिर प्रशासक की छवि अब भी उनके साथ है। ग्रामीण इलाकों में नीतीश को "काम करने वाला मुख्यमंत्री" कहा जाता है। आरजेडी के लिए यह धारणा तोड़ना आसान नहीं होगा। नीतीश के खिलाफ असंतोष मौजूद है, लेकिन वह किस सीमा तक वोट में बदलेगा, यह निश्चित नहीं। अगर एनडीए मतदाता एकजुट रहा, तो आरजेडी की संभावनाएं सीमित रह जाएंगी।

तेजस्वी यादव युवा और ऊर्जावान हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है "विश्वसनीयता"। लोगों के मन में अब भी यह प्रश्न है कि क्या वे लालू युग की राजनीति से अलग एक नए बिहार की परिकल्पना पेश कर पाएंगे? आरजेडी ने जब 15 वर्षों तक सत्ता संभाली थी, तब "जंगलराज" का आरोप उस पर चस्पा हुआ था। अब अगर तेजस्वी उस छवि को तोड़कर अपनी अलग पहचान बना पाए, तो यह चुनाव उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बिहार के मतदाता आज रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार से बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। राज्य में निवेश का माहौल अभी भी कमजोर है। अगर आरजेडी इन मुद्दों पर ठोस विज़न पेश करे, तो जनता उसे एक मौके के रूप में देख सकती है। लेकिन अगर वही पुरानी जातीय रेखाओं में उलझी रही, तो बदलाव का सपना फिर अधूरा रह जाएगा। आरजेडी के पास इस बार मौका है, माहौल भी कुछ हद तक अनुकूल है, और जनता में बदलाव की चाह भी मौजूद है।

सियासी गहमागहमी

बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को पाठ पढ़ाने क्यों पहुंचे?

लगता है कांग्रेस में अब राजनीति एक विषय नहीं, बल्कि एक कोर्स बन गया है और राहुल गांधी उसके मुख्य प्रशिक्षक। बिहार चुनाव के बीच जब हर पार्टी रणनीति, सोशल मीडिया और गठबंधन की गुत्थियों में उलझी है, तब राहुल ने सोचा "पहले बुनियादी बातें सिखा दूँ, फिर लड़ाई लड़ी जाएगी!" दरअसल, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को राजनीति सिखाना वैसा ही है जैसे परीक्षा से एक दिन पहले बच्चों को A, B, C सिखाना। पार्टी की हालत ऐसी है कि नेता ज्यादा हैं, मतदाता कम। शायद राहुल जी को लगा होगा कि "जनता से कैसे बात करें, मंच पर कैसे चढ़ें और भाषण में किस वाक्य पर तालियां बजवाएं" यह भी अब पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। बिहार के राजनीतिक तापमान में जहाँ हर कोई सीटों की गणना में व्यस्त है, वहीं कांग्रेस 'ट्रेनिंग सत्र' आयोजित कर रही है। असल में राहुल गांधी की यह कवायद बताती है कि कांग्रेस अब भी तैयारी के दौर में है, चुनाव तो बस संयोग से आ गया। बाकी पार्टियाँ मैदान में खेल रही हैं, और कांग्रेस अब भी व्हाइटबोर्ड पर समझा रही है "राजनीति क्या होती है?"

MP में मछली कारोबारी पर चल रही कार्रवाही क्यों थम गई?

मध्यप्रदेश की राजनीति में पानी हमेशा गंदा ही रहा है, पर इस बार मामला सचमुच "मछली" से जुड़ा है। कुछ समय पहले तक प्रशासनिक जाल इतनी तेजी से डाला गया था कि लगा राज्य में अब भ्रष्टाचार नहीं, बस मछली पकड़ने की होड़ चल रही है। लेकिन अचानक कार्रवाइयों की लहर थम गई, और अब सन्नाटा है जैसे तालाब में कोई बड़ी मछली बच निकली हो। कहते हैं, जब मछली बड़ी होती है तो जाल छोटा पड़ जाता है। लगता है, जांच एजेंसियों को भी यह अहसास हो गया। शुरू में सब कुछ "पारदर्शिता" के नाम पर हुआ छापे, जब्ती, बयानबाजी पर जैसे ही मामला ऊपरी सतह को छूने लगा, पानी में बुलबुले उठे और कार्रवाई ठंडी पड़ गई। जनता अब यह समझने लगी है कि हमारे यहाँ कानून का जाल हमेशा छोटी मछलियों के लिए ही बुना जाता है। बड़ी मछलियाँ तो पहले से जानती हैं कि कब पानी मटमैला करना है और कब किनारे सरक जाना है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

महाराष्ट्र में 1800 करोड़ की सरकारी जमीन, जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई।
ये है 'जमीन चोरी', उस सरकार की, जो खुद 'वोट चोरी' से बनी है। उन्हें पता है, चाहे जितना भी लूटें, वोट चोरी कर फिर सत्ता में लौट आएंगे।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश सरकार ने जिस आधी-अधूरी तैयारी के साथ प्रदेश में मतदाता सूचियों की जाँच अर्थात SIR की प्रक्रिया शुरू की है, उसने मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया का मजाक बना दिया है।
प्रदेश के बहुत से जिलों में मतदाता BLO का इंतजार कर रहे हैं और BLO फ़ॉर्म मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
हालत यह है कि जिलों में अभी तक फ़ॉर्म के प्रिंटआउट तैयार नहीं हुए हैं और न BLO को दिए गए हैं।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

राजस्थान की माटी के लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है गजेन्द्र सिंह शेखावत

समता पाठक/जगत प्रवाह

गजेन्द्र सिंह शेखावत एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ और प्रतिष्ठित नेता हैं, जिनकी पहचान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। वह 2024 से संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ने अपनी राजनीति की यात्रा जोधपुर से शुरू की और आज वह लोकसभा में जोधपुर के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में, जोधपुर और देश भर में पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को नई दिशा और प्रोत्साहन मिल रहा है। गजेन्द्र सिंह शेखावत का जन्म राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर में हुआ। उनके पिता, शंकर सिंह शेखावत, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे और उनके काम के कारण वे अक्सर राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात रहते थे। इस वजह से उन्होंने ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कई अलग-अलग स्कूलों में पूरी की। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से की, जहाँ से उन्होंने कला में मास्टर डिग्री और दर्शनशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनके शिक्षा के सफर ने उन्हें एक सशक्त और विचारशील नेता बनने के लिए प्रेरित किया।

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। 1992 में, वह जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और इस चुनाव में उन्हें अब तक के किसी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) समर्थक से अधिक वोट मिले। इसके बाद, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्य किया और राजस्थान राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। 2014 में, वह 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से सबसे बड़ी विजय प्राप्त की, जिसमें उन्होंने 4,10,051 वोटों से जीत हासिल की। एक सांसद के रूप में उनके कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि जोधपुर हवाई अड्डे का विस्तार था, जो पिछले 18 वर्षों से स्थानीय लोगों द्वारा लगातार उठाया जा रहा था। सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के लिए प्रसिद्ध, गजेन्द्र सिंह शेखावत क्यूरा पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय राजनेता हैं। उनके क्यूरा प्रोफाइल पर 83,749 से अधिक फॉलोवर्स हैं और उनके उत्तरों को 8 मिलियन बार देखा गया है। इसके अलावा, उन्होंने भारतीय खेल परिषद (AICS) के सदस्य और वित्त पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 3 सितंबर 2017 को, उन्हें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। 2019 के आम चुनावों में, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 2.74 लाख वोटों से हराया। 31 मई 2019 को, गजेन्द्र सिंह शेखावत जलशक्ति मंत्री के रूप में शपथ ली और इस पद पर उन्होंने देश की जल संबंधित नीतियों में सुधार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। चुनावी राजनीति में प्रवेश करने से पहले, गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कई मंचों और संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह स्वदेशी जागरण मंच के सह-संयोजक थे, जो संघ परिवार का आर्थिक विंग है और सीमा जन कल्याण समिति के महासचिव भी रहे। यह समिति सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों और कस्बों को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। महासचिव के रूप में उन्होंने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को लेकर एक दूसरी रक्षा पंक्ति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा, उन्होंने नागरिक सुरक्षा के प्रभाव को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत-पाकिस्तान सीमा पर 40 स्कूल और चार छात्रावास स्थापित किए, जिससे स्थानीय लोगों को सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिला।

विश्व विज्ञान दिवस पर विशेष

विज्ञान से विकास, लेकिन विवेक भी जरूरी

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

विज्ञान आधुनिक सभ्यता की धड़कन है, एक ऐसा इंजन जो समाज को गति देता है, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद दिलाता है कि "विकास तब तक सार्थक नहीं जब तक उसमें विवेक और शांति का समावेश न हो।" हर साल 10 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व विज्ञान दिवस इसी सोच का प्रतीक है, यह दिवस बताता है कि वैज्ञानिक प्रगति तभी अर्थपूर्ण है जब वह समाज, शांति और मानवता के हित में हो।

विज्ञानः विकास का इंजन

मानव इतिहास में विज्ञान ने वह कर दिखाया है जो कभी चमत्कार कहा जाता था। बिजली ने अंधकार मिटाया, इंटरनेट ने सीमाएँ तोड़ीं, चिकित्सा ने जीवन बढ़ाया और अंतरिक्ष अनुसंधान ने हमें ब्रह्मांड की गहराइयों तक पहुँचाया। आज विज्ञान प्रयोगशालाओं से निकलकर हर व्यक्ति के जीवन में समाया हुआ है, कृषि में ड्रोन, बैंकिंग में एआई, शिक्षा में डिजिटल लर्निंग और स्वास्थ्य में जेनेटिक थेरेपी सब विज्ञान की देन हैं। परंतु यह प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है: क्या यह विकास मानवता को संतुलित दिशा में ले जा रहा है? क्योंकि विज्ञान तभी सार्थक है जब उसका अंतिम उद्देश्य केवल तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, समानता और शांति को बढ़ाना हो।

शांतिः विज्ञान का नैतिक आधार

विज्ञान ने मानव को शक्ति दी है, लेकिन वही शक्ति विनाश का कारण भी बन सकती है। परमाणु ऊर्जा का आविष्कार सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि थी, पर उसी ऊर्जा से बने बमों ने हिरोशिमा और नागासाकी को राख में बदल दिया। यह इतिहास हमें सिखाता है कि ज्ञान तब तक सुरक्षित नहीं जब तक उसके साथ विवेक और नैतिकता न जुड़ी हो। आज जब विश्व जलवायु संकट, हथियारों की दौड़ और साइबर युद्ध जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब "विज्ञान के साथ विवेक" की भावना पहले से कहीं अधिक जरूरी है। विज्ञान का असली उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है न कि केवल मशीनों को तेज और मुनाफों को बड़ा करना।

विज्ञान और समाजः साझी जिम्मेदारी

विज्ञान केवल वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि समाज के हर नागरिक की चेतना में जीवित रहना चाहिए। हर व्यक्ति की भूमिका है यह सुनिश्चित करने में कि वैज्ञानिक उपलब्धियाँ समाज के हर वर्ग तक पहुँचें। क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति तभी उपयोगी है जब वह गरीबों और वंचितों के जीवन को आसान बनाए। तकनीक तभी सफल है जब वह पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास दे। और आविष्कार तभी सार्थक है जब वह पृथ्वी की रक्षा करे। आज का युग हमें यह चेतावनी भी दे रहा है- प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक संकट हैं। इसलिए विज्ञान को केवल "ज्ञान" नहीं, "जिम्मेदारी" के रूप में देखना होगा। भविष्य की सोचः सतत विकास की दिशा 21वीं सदी का विज्ञान हमें सतत विकास (Sustainable Development) की राह दिखा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और क्वांटम साइंस जैसे क्षेत्र इंसान की क्षमताओं को नई दिशा दे रहे हैं। परंतु अगर इन तकनीकों के पीछे मानवीय दृष्टि और नैतिक उद्देश्य न हों तो यही विकास बेरोजगारी, असमानता और तनाव को जन्म दे सकता है। भारत में भी अब "हरित प्रौद्योगिकी" और "स्वदेशी नवाचार" पर बल दिया जा रहा है। उत्तराखंड के ग्रीन इनोवेशन मॉडल, कृषि में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई या ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा- यह सब उदाहरण हैं कि विज्ञान का उपयोग पर्यावरण और समाज दोनों की भलाई में कैसे किया जा सकता है।

प्रेरणादायक संदेशः विज्ञान का मानवतावादी स्वरूप

भारत का दर्शन हमेशा से विज्ञान और अध्यात्म का संगम रहा है। यहाँ ऋषियों ने प्रयोग किए, प्रश्न पूछे और प्रकृति से संवाद किया। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था। "विज्ञान का उपयोग तभी सार्थक है जब वह जीवन को बेहतर बनाने के साथ-साथ मनुष्य को बेहतर इंसान बनाए।" हमें अपने बच्चों में यही सोच जगानी होगी- कि विज्ञान केवल मशीनें नहीं बनाता, वह मनुष्य के भीतर जिम्मेदारी भी जगाता है। उन्हें यह सिखाना होगा कि जिज्ञासा के साथ करुणा भी जरूरी है, और विकास के साथ संतुलन भी।

विकास हो लेकिन शांति के साथ

विज्ञान ने हमें अंधकार से प्रकाश तक पहुँचाया है, लेकिन यह यात्रा अधूरी है यदि हम विवेक को साथ न रखें। "Responsible Science" - यही 21वीं सदी का मंत्र है। हमें ऐसा विज्ञान चाहिए जो न केवल तेजी से आगे बढ़े, बल्कि धरती और मानवता की रक्षा भी करे। इस विश्व विज्ञान दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम विज्ञान को मानवता की सेवा का माध्यम बनाएँगे, हर नवाचार में शांति, नैतिकता और करुणा का भाव जोड़ेंगे और एक ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएँगे जहाँ विकास का हर कदम विवेक और संतुलन से जुड़ा हो। क्योंकि सच्चा विकास वही है जो शांति, ज्ञान और नैतिकता के संग चले, यही विज्ञान का वास्तविक, मानवीय और प्रेरणादायक स्वरूप है।

गुप्त परमाणु हथियार परीक्षण की आशंकाएं

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा 'बयान-बम' फोड़ा है। विवादित बयानों को लेकर चर्चित ट्रंप ने दावा किया है कि चीन और पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण में लगे हैं। रूस और उत्तर कोरिया भी परमाणु परीक्षण कर अपने हथियारों की ताकत टटोल रहे हैं। ये देश कभी भी यह बात स्वीकारने को तैयार नहीं हैं कि वे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ये देश भूमि की बहुत गहराई में परीक्षण करते हैं। इसलिए इनके परीक्षण की आहट किसी के कानों में नहीं गूंजती है। इन देशों के लोग खुले समाज के हिस्सा नहीं हैं, अतएव यहां की जानकारियां गोपनीय बनी रहती हैं। यह बात ट्रंप को इसलिए कहनी पड़ी, क्योंकि अमेरिका 30 साल बाद अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से करने का फैसला ले चुका है। इसलिए उन्होंने अपनी सरकार के फैसले को पाक और चीन के परीक्षणों के परिप्रेक्ष्य में तार्किक ठहराने के लिए कही है। यह बात ट्रंप ने न्यूज चैनल सीबीएस से बात करते हुए कही है।

दरअसल रूस द्वारा ट्रंप से पूछा गया था कि 'क्या वे एडवांस न्यूक्लियर-कैपेबल सिस्टम, जिसके द्वारा पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन गतिविधि शामिल है, उसके परीक्षण के बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण भी करेंगे?' इसके उत्तर में ट्रंप ने कहा, 'उनके पास किसी भी दूसरे देश से अधिक परमाणु हथियार हैं। इन हथियारों से दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है। हम इन्हें नहीं परखते। किंतु जब दूसरे देश परीक्षण कर रहे हैं, तब हमें भी करने की जरूरत है। याद रहे, ट्रंप ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान नगर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने से पहले अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षणों को फिर से शुरू करने का बयान दिया गया था। पानी के भीतर पोसाइडन ड्रोन प्रणाली एक ऐसी तकनीक है, जिसमें रोबोटिक वाहन पानी के नीचे सक्रिय रहते हैं। ये स्वायत्त रूप से संचालित रहने के साथ इन्हें रिमोट के जरिए दूर से भी संचालित किया जा सकता है। ये ड्रोन पनडुब्बी वाहनों के समान होते हैं, जो बिना किसी मानव के पानी के नीचे संचालन और अनुसंधान के लिए होते हैं।

किसी भी परमाणु हथियार संपन्न देश को परमाणु परीक्षण की जरूरत इसलिए होती है, क्योंकि परमाणु बम के लिए जरूरी यूरेनियम को संवर्धन (एनरिच) करना होता है। यह प्रक्रिया एक तकनीकी परीक्षण है। परमाणु परीक्षण की घोषणा किसी भी देश की ऐसी यौद्धिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह शत्रु देश को अपनी ताकत का अहसास कराता है। भारत ने 1998 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। अब चीन और पाक द्वारा गोपनीय रूप में परमाणु परीक्षण की बात सामने आई है। अतएव इन देशों से भारत को परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। इसलिए भारत को भी अपनी परमाणु हथियार दागने की तकनीक का परीक्षण करना जरूरी हो गया है। हालांकि भारत का सिद्धांत पहले परमाणु हमला नहीं करने का है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि अब हम इस वचन के पालन के प्रतिबद्ध नहीं हैं। पहले भी हमला कर सकते है। वैसे भी भारत ने अब तक परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने वाली संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। शायद इसीलिए ट्रंप को कहना पड़ा है कि 'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के विरुद्ध भारत परमाणु हमले के लिए तत्पर था। इस कारण पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुझसे निवेदन किया कि आप बीच में आकर युद्ध रोकें, वरना पाक में लाखों लोग मारे जाएंगे।'

बहरहाल, ट्रंप के किसी भी दावे की पुष्टि भारत नहीं करता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया के कई देश न केवल परमाणु परीक्षण करने में लगे हैं, बल्कि घातक परमाणु हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ में भी लगे हैं। स्टॉकहोम स्थित 'अंतराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान' (एसआईआरआई) के एक अध्ययन ने दावा किया है कि चीन के पास 350, पाकिस्तान 165 और भारत के पास जनवरी 2021 तक 156 परमाणु हथियार मौजूद थे। ऐसा लगता है कि ये तीनों पड़ोसी देश अपने परमाणु शस्त्रागारों का विस्तार कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस समय 13,080 परमाणु हथियार दुनिया के देशों के पास हैं। इनमें 90 प्रतिशत से ज्यादा रूस और अमेरिका के पास हैं। इनके अलावा ब्रिट्रेन, फ्रांस, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी हथियारों का बड़ा जखीरा है। चीन परमाणु हथियारों की संख्या के बढ़ाने के साथ उनका तकनीकी रूप से आधुनिकीकरण भी कर रहा है। सऊदी अरब, मिश्र, भारत, आस्ट्रेलिया और चीन ने 2016 से 2020 के बीच सबसे ज्यादा हथियार आयात किए हैं। वैश्विक स्तर पर हथियारों के आयात में सऊदी अरब की हिस्सेदारी 11 और भारत की 9.5 प्रतिशत है। इस समय रूस के पास 6,255, अमेरिका 5,550, फ्रांस 290, ब्रिट्रेन 225, इजराइल 90 और उत्तर कोरिया के पास 40-50 परमाणु हथियार हैं। ट्रंप तो सरेआम कह रहे हैं कि हमारे पास दुनिया को 150 बार तहस-नहस करने की परमाणु क्षमता है।

अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए के पूर्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारी केविन हलबर्ट की बात मानें तो पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक देशों में से एक है। पाकिस्तान की यह खुंखार और डरावनी सूरत इसलिए बन गई है, क्योंकि तीन तरह के जोखिम इस देश में खतरनाक ढंग से बढ़ रहे हैं। एक आतंकवाद, दूसरे ढह रही अर्थव्यवस्था और तीसरे परमाणु हथियारों का जरूरत से ज्यादा भंडारण। आर्थिक संकट के ऐसी ही बदतर हालात से उत्तर कोरिया जूझ रहा है। मानव स्वभाव में प्रतिशोध और ईर्ष्या दो ऐसे तत्व हैं, जो व्यक्ति को विवेक और संयम का साथ छोड़ देने को मजबूर कर देते हैं। इस स्वभाव को क्रूरतम परिणति में बदलते हम अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर किए परमाणु हमलों के रूप में देख चुके हैं। अमेरिका ने हमले का जघन्य अपराध उस नाजुक परिस्थिति में किया था, जब जापान इस हमले के पहले ही लगभग पराजय स्वीकार कर चुका था। पाक इस समय इसी क्रूरतम मानसिकता से गुजर रहा है। ऐसे में यदि वह चीन के साथ परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। ट्रंप जो बात कह रहे हैं, वह हवा-हवाई होने की बजाय संभव है कि उनकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर कही गई हो?

भाऊ साहेब भुस्कुटे शासकीय महाविद्यालय में युवा उत्सव मनाया

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। जिला स्तरीय युवा उत्सव के अंतर्गत भाऊ साहेब भुस्कुटे शासकीय महाविद्यालय में परिचर्चा, वाद-विवाद, एकांकी, मूक अभिनय एवं प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य और डॉ. अरुण कुमार सिकरवार के द्वारा की गई। कार्यक्रम में जिला संगठन मीनाक्षी यादव एवं प्रतिवाद समिति की ओर से डॉ. संजय पटवा एवं डॉ. राकेश परस्ते कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। परिचर्चा में हरदा डिग्री कॉलेज हरदा की ओर से छात्र चर्चिता खेतान में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

वाद विवाद प्रतियोगिता के अंतर्गत पक्ष में अनमोल राजपूत हरदा आदर्श महाविद्यालय हरदा एवं विपक्ष में इशिका ठाकुर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख अभिनय प्रतियोगिता के अंतर्गत हरदा डिग्री कॉलेज हरदा ने प्रथम स्थान जबकि एलबीएस महाविद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। एकांकी विद्या के अंतर्गत भाऊ साहेब भुस्कुटे शासकीय महाविद्यालय

के विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा प्रश्न मंच प्रतियोगिता में हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के विद्यार्थी प्रथम स्थान पर रहे वहीं द्वितीय स्थान पीएम श्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस हरदा के विद्यार्थियों ने प्राप्त किया। इन प्रतियोगिताओं के निर्णायक के रूप में डॉ. सुनील जोशी, मनीष सोनकिया एवं श्रीमती सुचिता दुबे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुनीत काशिव के द्वारा किया गया एवं आभार डॉक्टर सुनील बीरासी के द्वारा व्यक्त किया गया।

बाइक से 2.50 लाख रुपए नगदी से भरा थैला चुराने वाले बदमाश अमित सासी को राजगढ़ से पुलिस ने पकड़ा

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। पिपरिया में बीच बाजार महिंद्रा शोरुम के सामने से फरियादी की मोटरसाइकिल पर रखे बैग से ढाई लाख रुपए नगदी चोरी होने की घटना के बाद पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा एस थोटा द्वारा पिपरिया एसडीओपी सहित थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद पुलिस टीम ने लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हुए और हाईटेक तकनीकी सिस्टम साइबर सेल का इस्तेमाल करते हुए आखिर शातिर बदमाश को राजगढ़ से खोजकर नगदी सहित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में किया। जानकारी के अनुसार दिनांक 26.09.2025 को फरियादी शंकर पिता स्व. प्रेमचंद्र पटैल उम्र 48 साल निवासी ग्राम गूजरखापा, तह. सोहागपुर ने थाना पिपरिया उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि वह सीआईएसएफ का जवान है जो छुट्टी लेकर ट्रेक्टर की किस्त जमा करने स्टेट बैंक शाखा सोहागपुर से रुपये निकालकर

महिन्द्रा शोरुम पिपरिया आया था। जहां किसी अज्ञात व्यक्ति में फरियादी की मोटर सायकल के बैग में रखे 2,50,000/- रुपये चोरी कर लिये। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पिपरिया में अपराध क्रं. 378/2025 धारा 303(2) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम साई कृष्णा (भापुसे) द्वारा थाना प्रभारी पिपरिया को त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। थाना प्रभारी पिपरिया द्वारा मय हमराह बल के टीम गठित कर अज्ञात आरोपी की पतारसी करने घटना स्थल पहुंचकर जानकारी एकत्रित करते हुए अनुसंधान टीम द्वारा लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे चेक किये गए एवं तकनीकि संसाधनों की सहायता से पुलिस टीम द्वारा आरोपी की पहचान अमित सासी पिता रमेशचन्द्र सासी 20 वर्ष निवासी लक्ष्मीपुरा थाना छबड़ा जिला बांरा हाल कढिया सासी जिला राजगढ़ के रूप में कर पुलिस टीम द्वारा आरोपी को अभिरक्षा में लेकर 2,50,000 रु. जब्त किया गया।

दिखने लगे दिल्ली में प्रदूषण के तेवर

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

पूरे देश में आबोहवा तेजी से खराब हो रही है। 11 मार्च, 2025 को प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में हैं, जिसमें असम का बर्नीहाट शीर्ष पर है। वैसे सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में और विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हालात और भी चिंताजनक है। हर वर्ष अक्टूबर नवंबर महीना या यह कहा जाए कि हल्की ठंड आते ही दिल्ली में प्रदूषण लोगों के जीवन में जहर घोलने लगता है। विडंबना यह है कि देश की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के नाम से जाना जा रहा है। द वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स नामक संस्था ने दुनिया की दस सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानियों की सूची में दिल्ली को शीर्ष पर रखा था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पिछले कुछ वर्षों से लगातार विश्व में शीर्ष देशों में शामिल है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है। कुछ ही दिन पहले डीटीयू पर वायु गुणवत्ता सूचनांक (AQI) 402 के पार पहुंच चुका था। भला हो बारिश का और तेज हवा का जिसने प्रदूषण को थोड़ा कम किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर बुलेटिन के अनुसार प्रदूषण की मुख्य वजह पीएम- 10 और एनओ- 2 रहा। पीएम- 10 धूल और एनओ- 2 गाड़ियों के धुएं से निकलता है। दिल्ली एनसीआर के नागरिकों के लिए घातक प्रदूषण में जीना नियति बन गया है। वायु प्रदूषण मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के लोग इस वर्ष भी भयंकर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। राजधानी के लोगों को खराब हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। डॉक्टर इसके लिए आगाह कर रहे हैं कि बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। फिर भी इस पर लगाम लगती नही दिख रही जो बेहद चिंताजनक है। वायु प्रदूषण की मार शासन-प्रशासन की घोर लापरवाही को ही इंगित करता है। आखिर ऐसा क्यों है कि सरकारें वायु प्रदूषण को नियंत्रित नही कर पा रही है? पराली अर्थात फसलों के अवशेष जलाने की समस्या आज की नही बल्कि पिछले दो दशकों से चली आ रही है। पहले सरकारें मुंह छिपाती थी और यह मानने को तैयार नहीं होती थीं कि दिल्ली एनसीआर ही नही पूरे उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर में वायु प्रदूषण के पीछे पराली का धुआं है लेकिन अब वे ऐसा मानने लगे हैं। बावजूद इसके वे पराली को जलने से नही रोक पा रहे हैं। योजनाएं तो बन रही हैं लेकिन अमल सही ढंग से नही हो पा रहा है। जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है समस्या से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं ऐसा दावा करते वह थकती नही है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो दिल्ली के गुरु तेग बहादुर और लोक नायक अस्पताल में सरकार अन्य सरकारी सुविधाओं के विस्तार से पहले प्रदूषण क्लिनिक खोलने का विचार कर रही है।

सर्दी के मौसम में यह बदहाल स्थिति हर साल आती है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में सांस, दमा, हृदय, फेफड़े, आंत, नेत्र, त्वचा, गले, नाक आदि रोगों के पीड़ितों की संख्या अन्य मौसम के मुकाबले बेहद बढ़ जाती है। अस्पतालों में बढ़ती संख्या इसका सबूत है। कुछ लोग कुछ समय के लिए देश छोड़कर जा रहे हैं। आम लोग प्रदूषण से परिचित तो हैं लेकिन उन्हें रोकने के लिए सजग नही जो हवा को जहरीला बनाते हैं। आखिर क्या कारण है कि लोग प्रदूषण के मामले में अपने दायित्व को समझने के लिए तैयार नहीं हैं? प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली ही नही बल्कि लोगों के द्वारा अत्याधिक निजी वाहनों का उपयोग, निर्माण कार्य, लकड़ियां एवं पत्तों को जलाना, कूड़ा कड़कट फैलाना आदि भी कारण है। शासन प्रशासन को अपनी सक्रियता बढ़ाए जाने के साथ लोगों पर सख्ती भी करना चाहिए जो जानबूझकर प्रदूषण फैलाते हैं। वायु प्रदूषण को दूर करने में कोई कोताही इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि एक तो उससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और दूसरे देश की अंतराष्ट्रीय स्तर पर छवि भी खराब हो रही है।

प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता, क्या कमलनाथ के विजन को अपना सकती है सरकार?

(पेज 1 का शेष)

एक दूरदर्शी पथ पर आगे बढ़ने की आवश्यकता

आज जब मध्य प्रदेश अपने स्थापना दिवस के जश्न की खुशबू में भी भविष्य की चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि कमलनाथ का विजन केवल एक राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं, बल्कि प्रदेश की वास्तविक आवश्यकताओं का प्रतिबिंब है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक इतना अनुभवी और दूरदर्शी नेतृत्व, जिसकी योजनाएं पूरी तरह से क्रियान्वयन के लिए तैयार थीं, उन्हें पूरा मौका नहीं मिल सका। आज मध्य प्रदेश की किसी भी सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर, कमलनाथ के युवा-केंद्रित, किसान-हितैषी और कौशल-आधारित विकास मॉडल से मार्गदर्शन ले। उनके द्वारा बुने गए उन्नत भविष्य के ताने-बाने को अपनाकर ही हम मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य केवल जश्न मनाना नहीं, बल्कि सार्थक, सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। जब तक प्रदेश के हर युवा को सम्मानजनक रोजगार, हर किसान को उसका हक और हर महिला को सशक्तिकरण का अवसर नहीं मिलता, तब तक स्थापना दिवस का उत्सव अधूरा है। कमलनाथ का विजन ही वह दूरदर्शी पथ है, जिस पर चलकर हम इस सार्थकता को हासिल कर सकते हैं।

उनके कार्यकाल में उठाए गए प्रमुख कदम और उनका विज़न इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है-

किसानों को सशक्त बनाने का संकल्प

कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण फैसला किसानों की कर्जमाफी था, जो उनके 'जय किसान ऋण मुक्ति योजना' के तहत आया। उन्होंने किसानों के 02 लाख तक के कर्जमाफ करने की प्रक्रिया शुरू की।

मुख्य उपलब्धिः विभिन्न स्रोतों के अनुसार उनके 15 महीने के कार्यकाल में 30 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया गया, जिससे किसानों को तत्काल वित्तीय राहत मिली और कृषि क्षेत्र में नया विश्वास जागा।

दूरदर्शिताः उनका लक्ष्य कृषि को लाभ का धंधा बनाना था, ताकि कर्ज के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर न हों। फसल बीमा और सिंचाई परियोजनाओं पर भी जोर दिया, ताकि किसानों की आय में निरंतर वृद्धि हो सके।

युवाशक्ति और कौशल विकास पर ज़ोर

मध्य प्रदेश में रोजगार की तलाश में भटक रहे पढ़े-लिखे युवाओं की बड़ी संख्या है। कमलनाथ का विजन था कि युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब क्रिएटर' बनाया जाए और उन्हें प्रदेश में ही रोजगार मिले।

मुख्य कदमः कमलनाथ ने मेगा स्किल सेंटरों की स्थापना, युवा स्वाभिमान योजना और नई औद्योगिक नीति के माध्यम से प्रदेश में निवेश और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि जब तक युवा सशक्त नहीं होंगे, प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती।

दूरदर्शिताः उनका स्पष्ट मत था कि केवल सरकारी नौकरियों से रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण और नई तकनीकों से युवाओं को जोड़कर ही उन्हें स्थायी रोजगार दिया जा सकता है।

सामाजिक न्याय और वंचितों का उत्थान

कमलनाथ के नेतृत्व में सामाजिक न्याय के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जो समावेशी विकास के उनके विजन को दर्शाते हैं।

पिछड़ा वर्ग को आरक्षणः अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। यह कदम प्रदेश की बड़ी आबादी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास था।

आदिवासी कल्याणः उन्होंने आदिवासी पलायन को रोकने के लिए उनके क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय संसाधनों पर उनके अधिकार को मजबूत करने की योजना बनाई। उनका लक्ष्य था कि आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और जमीन से जुड़े रहते हुए विकास के मुख्यधारा में लाया जाए।

महिलाओं का सशक्तिकरणः महिलाओं के लिए स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना और उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए विशेष कार्यक्रमों पर बल दिया गया।

छिंदवाड़ा मॉडलः संपूर्ण प्रदेश के लिए प्रेरणा

कमलनाथ का राजनीतिक कर्म क्षेत्र छिंदवाड़ा, उनके विकास के विजन का एक जीता-जागता प्रमाण है। दशकों से उन्होंने छिंदवाड़ा को एक ऐसे 'विकास मॉडल' में बदला, जिसकी तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं।

मॉडल के मुख्य तत्वः छिंदवाड़ा मॉडल केवल बेहतर सड़कें और बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि सोयाबीन उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की समृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का उच्चीकरण और स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के माध्यम से स्थानीय रोजगार सृजन इसका मूल है।

प्रदेशव्यापी योजनाः कमलनाथ का विजन था कि इसी समग्र विकास मॉडल को जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल सहित प्रदेश के हर संभाग में लागू किया जाए। उनका सपना था कि प्रदेश का हर जिला, निवेश और रोजगार के लिए एक आत्मनिर्भरता का केंद्र बने।

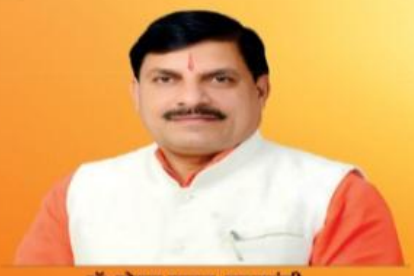

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश
अनंत संभावनाएं

उद्योग एवं रोज़गार वर्ष 2025

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

व्यापक निवेश अवसर

सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना

योजना के प्रमुख उद्देश्य

- मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी को कम मूल्य पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराना
- ट्रांसमिशन हानि कम करना एवं सीधे खपत स्थल पर बिजली पहुंचाना
- 33/11 केवी उपकेंद्रों पर ओवरलोडिंग, लो-वोल्टेज और पावर कट की समस्या कम करना
- किसान को सिंचाई के लिये दिन में बिजली उपलब्ध कराना

नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार

- सब-स्टेशन की 100% क्षमता तक की परियोजनाओं की स्थापना
- परियोजनाओं को पीएम कुसुम-सी योजनांतर्गत उपलब्ध केंद्रीय अनुदान का लाभ लेने का विकल्प
- 1900 से अधिक विद्युत सबस्टेशन एवं 14500 मेगावॉट क्षमता सौर परियोजनाओं के चयन हेतु उपलब्ध
- पीएम कुसुम योजना में 3.45 लाख पम्प का लक्ष्य
- वोकल फॉर लोकल - स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश एवं रोज़गार सृजन का उचित अवसर
- वित्त पोषण की सुगमता के लिए बैंकों से समन्वय
- परियोजनाओं में AIF के तहत 7 वर्षों तक 3% ब्याज में छूट
- Reactive Power प्रबंधन से अतिरिक्त आय

RO No. D19201/25

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)